राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3842/2020

रत्ती पुत्र असीना, निवासी मिर्चुनी, थाना टपूकड़ा, जिला, अलवर, राज.

----शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. बिलालुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी मिर्चुनी, थाना टपूकड़ा, जिला अलवर, राज.
3. साकिर पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी मिर्चुनी, थाना टपूकड़ा, जिला अलवर, राज.
4. कुतबुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी मिर्चुनी, थाना टपूकड़ा, जिला अलवर, राज.
5. लियाकत अली पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी मिर्चुनी, थाना टपूकड़ा, जिला, अलवर, राज.

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(यों) के लिए	:	**श्री** आर के माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री कृतिन शर्मा
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	**श्री** अतुल शर्मा, पी.पी
		श्री राहुल तिवारी

माननीय श्री जस्टिस सुदेश बंसल

आदेश

01/02/2024

रिपोर्ट योग्य

1. शिकायतकर्ता ने धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत यह आपराधिक विविध याचिका दायर की है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थना की मांग की गई है:

> "अतः विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस आपराधिक विविध याचिका को स्वीकार किया जाए और सत्र प्रकरण संख्या 51/2019 राज्य बनाम बिलालुद्दीन एवं अन्य में विद्वान सत्र न्यायाधीश संख्या 2, तिजारा, अलवर द्वारा पारित दिनांक 27.02.2020 के आदेश को स्वीकार किया जाए तथा अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन को रद्द किया जाए-उत्तरदाता को कृपया अस्वीकार किया जाए।
>
> विद्वान ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के दौरान अभियुक्तों को अदालत के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सामग्री का उपयोग करने की अनुमति न दे और ऐसी सामग्री का उपयोग केवल बचाव पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान ही किया जा सकता है, यदि कोई हो।"

2. मुहम्मद के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया तथा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान आपराधिक मामले में "आरोप तय करने से पहले" के चरण में आरोपी उत्तरदाता संख्या 2 से 5 (अनुलग्नक 2) द्वारा और उनकी ओर से दायर दिनांक 28.01.2020 के एक आवेदन पर, ट्रायल जज ने, दिनांक 27.02.2020 के आदेश के तहत, एस.एच.ओ, पुलिस स्टेशन - टपूकड़ा, जिला - अलवर को न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं (i) घटना की तारीख यानी 20.08.2019 को मोबाईल नंबर 9982671312 का टावर लोकेशन, जो मुहम्मद-शिकायतकर्ता का है और (ii) घटना की तारीख यानी 20.08.2019 को पुलिस लाइन, अलवर के सामने स्थित एसबीआई के एटीएम से आरोपी साकिर अली की उपस्थिति से संबंधित सीसीटीवी फुटेज।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्तों द्वारा अपने बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए दोनों सूचनाएं प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, हालांकि, अभियुक्तों द्वारा आवेदन "आरोप तय करने से पहले" के चरण में दिया गया था और इसे ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दोनों सूचनाएं प्राप्त करके, अभियुक्त यह साबित करना चाहते हैं कि 20.08.2019 को हत्या की घटना के दिन, एफआईआर दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता-रत्ती, टपूकड़ा में मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए वोडाफोन कंपनी से उनके मोबाइल टावर की लोकेशन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था और साथ ही, अभियुक्त-साकिर अली के लिए एलीबाई की दलील लेने के लिए कि वह उस दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, बल्कि वह एसबीआई के एटीएम में मौजूद थे, इसलिए एसबीआई एटीएम का सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तों की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करें और उन्हें न्यायालय के माध्यम से अपने बचाव पक्ष के साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, या इसके विपरीत, बचाव पक्ष के साक्ष्य हेतु वर्तमान आपराधिक मामले के चरण तक पहुँचने से पहले निचली अदालत को ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इसलिए, निचली अदालत के न्यायाधीश ने अभियुक्तों के आवेदन को स्वीकार करके, वह भी "आरोप निर्धारण से पहले" के चरण में, अवैधता और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक अतिरिक्त या वैकल्पिक तर्क भी दिया है कि दिनांक 27.02.2020 के आदेश को पारित करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 16.07.2020 के तहत अभियोजन पक्ष को मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

फुटेज पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने और अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया था; इसके बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 23.07.2020 के आदेश के तहत आरोपी व्यक्तियों को चार पेन ड्राइव उपलब्ध कराने की अनुमति दी है, इसलिए, कम से कम ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जा सकता है कि वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के दौरान आरोपी व्यक्तियों को अदालत के माध्यम से प्राप्त ऐसी सामग्री का उपयोग करने की अनुमति न दे और ऐसी सामग्री को आरोपी व्यक्तियों द्वारा केवल उनके बचाव पक्ष के साक्ष्य के दौरान उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

4. सुना गया। विचार किया गया।

5. सर्वप्रथम, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य ने दिनांक 27.02.2020 के आदेश को चुनौती नहीं दी है और वर्तमान याचिका शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई है। इस दृष्टि से, विद्वान लोक अभियोजक ने वर्तमान याचिका में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह माननीय न्यायालय न्याय के उद्देश्य हेतु इसे उचित और उचित मानता है।

5. पैगंबर के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों और आक्षेपित आदेश तथा रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री के अवलोकन के बाद, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान सत्र मामला 20.08.2019 को पुलिस स्टेशन - टपूकड़ा, जिला - अलवर में दर्ज एफआईआर संख्या 228/2019 से उत्पन्न हुआ है। एफआईआर की प्रति रिकॉर्ड में (अनुलग्नक 1) के रूप में उपलब्ध है। पैगंबर-रत्ती द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि 20.08.2019 को लगभग 03:00 बजे, पैगंबर, उनके भाई रज्जाक और रहीस टपूकड़ा में श्री रुक्मू की दुकान पर बैठे थे और अचानक छह व्यक्ति मोटरसाइकिल और एक कार पर आए, अपने वाहनों से उतरे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इस हमले में उनके भाई रज्जाक की मौत हो गई इस एफआईआर पर, जांच के बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों-उत्तरदाता संख्या 2 से 5 के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 120-बी के साथ धारा 3/25 और 5/27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के लिए एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, वर्तमान सत्र मामला पंजीकृत किया गया और "आरोप तय करने से पहले" के चरण में, आरोपी व्यक्तियों ने 28.01.2020 (अनुलग्नक 2) दिनांकित एक आवेदन दिया। आवेदन में, कानून के किसी प्रावधान का संकेत नहीं दिया गया है, हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 91 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों के तहत

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

उक्त आवेदन पर विचार किया और फैसला सुनाया। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 27.02.2020 के आदेश के तहत आवेदन को अनुमति दी

6. दिनांक 27.02.2020 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने यह देखा है कि जांच के दौरान जांच अधिकारी के लिए संपूर्ण प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करना आवश्यक था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों द्वारा स्वयं को निर्देशित किया, जिसका उल्लेख आक्षेपित आदेश में किया गया है, जिसमें कानून के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी कि "जांच एक नाजुक, श्रमसाध्य और निपुण प्रक्रिया है। खोजी व्यावसायिकता के लिए नैतिक आचरण नितांत आवश्यक है"। इसके अलावा जांच अधिकारी "केवल ऐसे साक्ष्य के साथ अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए नहीं है जो अदालत को दोषसिद्धि दर्ज करने में सक्षम बना सके, बल्कि वास्तविक और बिना किसी लाग-लपेट के सच को सामने लाए।" इस प्रकार, आक्षेपित आदेश यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने देखा कि एफआईआर और अभियोजन पक्ष के मामले में आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, घटना की तारीख यानी 20.08.2019 को लगभग 03:00 बजे शिकायतकर्ता-रत्ती का मोबाइल टावर लोकेशन। साथ ही, उस प्रासंगिक समय पर आरोपी साकिर अली की उपस्थिति के संबंध में एसबीआई एटीएम से सीसीटीवी फुटेज भी वर्तमान आपराधिक मामले की जांच और सुनवाई के उद्देश्य के लिए आवश्यक, प्रासंगिक और वांछनीय साक्ष्य हैं, इसलिए तथ्यों की ऐसी पृष्ठभूमि में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में, आक्षेपित आदेश पारित किया गया था और संबंधित एसएचओ को ऐसी सामग्री पेश करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आदेश का विरोध करने के लिए उठाए गए तर्कों पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय धारा 91 सी.आर.पी.सी. के प्रावधान पर विचार करना उचित समझता है और तत्काल संदर्भ के लिए उसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "91. दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन-(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज होने का विश्वास है, समन

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

> जारी कर सकेगा या ऐसा अधिकारी लिखित आदेश जारी कर सकेगा, जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित होकर उसे पेश करे या उसे पेश करे।
> (2) इस धारा के अधीन किसी दस्तावेज या अन्य चीज को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अध्यपेक्षा का अनुपालन कर दिया है, यदि वह ऐसे दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय उसे प्रस्तुत करवाता है।
> (3) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित नहीं समझी जाएगी-
> (क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124, या बैंकर बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) को प्रभावित करने के लिए, या
>
> (ख) डाक या टेलीग्राफ प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू करना।"

8. धारा 91 सी.आर.पी.सी. न्यायालय या पुलिस थाने के किसी भी प्रभारी अधिकारी को किसी भी दस्तावेज़ या अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए समन या आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जो न्यायालय या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की राय में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी जाँच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय है। धारा 91 सी.आर.पी.सी. की भाषा का तात्पर्य है कि न्यायालय या संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी मामले की जाँच या आपराधिक मुकदमे के किसी भी चरण में शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन धारा 91 सी.आर.पी.सी. की भाषा स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं करती है कि इस प्रावधान का आह्वान कौन कर सकता है। तथापि, धारा 91 सी.आर.पी.सी. की भाषा से यह स्पष्ट है कि इस प्रावधान को लागू करने से पहले, न्यायालय या पुलिस की संतुष्टि, जैसा भी मामला हो, दस्तावेज या किसी अन्य चीज की आवश्यकता या वांछनीयता के संबंध में, जिसे तलब किया जाना है या प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाना है, अनिवार्य है।

9. इस संदर्भ में, **शकुंतला बनाम दिल्ली राज्य, 139 (2007) डीएलटी 178** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें यह माना गया है:

> "...4. यह स्थापित कानून है कि निष्पक्ष और न्यायसंगत जाँच किसी भी जाँच की पहचान है। जाँच अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने द्वारा एकत्रित साक्ष्यों को रोककर अभियोजन पक्ष के

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

मामले को मज़बूत करे। यदि कोई जाँच अधिकारी अपने द्वारा एकत्रित साक्ष्यों को रोक लेता है, तो अभियुक्त को उस साक्ष्य पर प्रतिक्रिया देने और न्यायालय से यह कहने का अधिकार है कि आरोप तय करते समय उस साक्ष्य को ध्यान में रखा जाए। आरोप तय करते समय न्यायालय अभियुक्त के बचाव पक्ष या अभियुक्त के पास मौजूद उन दस्तावेज़ों पर विचार नहीं कर सकता, जिन्हें अभियुक्त ने जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था या जो जाँच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले की जाँच के दौरान जाँच अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्यों पर विचार करे। यदि अभियुक्त द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है कि जाँच अधिकारी या अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ साक्ष्य या दस्तावेज़ जानबूझकर रोके गए हैं, ताकि न्यायालय के सामने सच्चाई सामने न आए, तो न्यायालय आरोप तय करने से पहले जाँच अधिकारी को पूरी जाँच प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है और केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। निष्पक्ष जाँच यह अधिकार अभियुक्त का है और इस अधिकार का प्रयोग अभियुक्त द्वारा आरोप-पत्र के समय किया जा सकता है और अभियुक्त न्यायालय से आग्रह कर सकता है कि वह जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर विचार करे, लेकिन उसे आरोप-पत्र का हिस्सा न बनाए। ... आपराधिक मुकदमा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ...”

(जोर दिया गया)

10. **नीलेश जैन बनाम राजस्थान राज्य [2006 सी.आर.आई.एल.जे. 2151]** के मामले में पैरा संख्या 17 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को पुनः उद्धृत करना अनुचित नहीं होगा, इस प्रकार:

> “यह दावा करना कोई तर्क नहीं है कि अभियुक्त अपने बचाव में अभियोजन पक्ष द्वारा रोके गए दस्तावेज़ों की माँग कर सकता है। बचाव पक्ष मुकदमे के पहले दिन से ही तैयार किया जाना चाहिए, न कि तदर्थ आधार पर। जब तक जाँच के दौरान एकत्र किए गए सभी साक्ष्य अभियुक्त को नहीं दिए जाते, तब तक उसे उचित बचाव प्रस्तुत करने से रोका जाता है। बचाव का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित "जीवन" और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के मौलिक अधिकार से प्राप्त होता है, एक भ्रामक अधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। कोई अभियुक्त के हाथ नहीं बाँध सकता, उसे अपने बचाव के लिए आवश्यक साक्ष्यों से वंचित नहीं कर सकता और फिर भी यह दावा नहीं कर सकता कि निष्पक्ष सुनवाई हो रही है। इसके अलावा, प्रासंगिक दस्तावेज़ों और साक्ष्यों की इस तरह की टुकड़ों में आपूर्ति

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

> मुकदमे को अनावश्यक रूप से लंबा खींचती है। न्यायालयों को कम से कम समय में न्याय देने का प्रयास करना चाहिए। लंबा मुकदमा न केवल अपनी प्रासंगिकता खो देता है, बल्कि न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को भी बढ़ाता है। ऐसी रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है जो न्यायालयों को कुशल और वादी-हितैषी बनाएँ और जो इससे लोगों को शीघ्र न्याय मिलना सुनिश्चित होगा। इस प्रकार, जो दस्तावेज़ या साक्ष्य तुरंत उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उन्हें अभियुक्त के बचाव में आने तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है...।"

(जोर दिया गया)

11. मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, शिकायतकर्ता-ईश्वर की ओर से इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि हत्या की घटना की तारीख और समय पर शिकायतकर्ता के मोबाइल टावर की लोकेशन और एसबीआई के एटीएम से सीसीटीवी फुटेज, जो यह दर्शाता है कि घटना के समय आरोपी साकिर अली मौके पर मौजूद नहीं था, उसके द्वारा किसी और के होने का दावा करने के लिए, साक्ष्य का आवश्यक और प्रासंगिक हिस्सा होगा, विशेष रूप से, ऊपर उल्लिखित एफआईआर के आरोपों को देखते हुए; ईश्वर के वरिष्ठ वकील का तर्क यह है कि आरोपी व्यक्ति स्वयं बचाव में अपने साक्ष्य पेश करते समय ऐसे साक्ष्य/रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं या उनके द्वारा दायर आवेदन को आरोप के चरण में अनुमति नहीं दी जा सकती है, अर्थात आपराधिक मुकदमे के चरण से पहले बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जहाँ तक हत्या के वर्तमान मामले में तलब की गई सामग्री की प्रासंगिकता का प्रश्न है, यह ध्यान देने योग्य है कि निचली अदालत ने स्वयं पहले यह माना था कि शिकायतकर्ता के मोबाइल टावर लोकेशन और अभियुक्तों में से एक, साकिर अली के सीसीटीवी फुटेज, वर्तमान आपराधिक मामले की सुनवाई में ठोस, आवश्यक, वांछनीय और प्रासंगिक साक्ष्य हैं, जिन्हें जाँच अधिकारी द्वारा जाँच के दौरान एकत्र किया जाना चाहिए था। आक्षेपित आदेश इस बात का एक निहित प्रतिबिंब प्रदान करता है कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले ही निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँच गई थी। इस प्रकार, इस सीमा तक, यह माना जा सकता है कि निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करने और टपूकड़ा पुलिस स्टेशन के संबंधित एसएचओ को अदालत के समक्ष ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अधिकार अपने अधिकार क्षेत्र में ही रखा है।

12. मुद्दा अभियुक्तों द्वारा इस उद्देश्य के लिए 28.01.2020 को एक आवेदन दायर करने के

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

अधिकार के संबंध में है और वह भी आपराधिक मुकदमे में "आरोप तय करने से पहले" के चरण में। इस संबंध में, यह न्यायालय पाता है कि धारा 91 सीआरपीसी की भाषा कहीं भी किसी अभियुक्त व्यक्ति पर इस प्रावधान में परिकल्पित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। हालाँकि, आमतौर पर धारा 91 सीआरपीसी के तहत कोई भी निर्देश या आदेश प्राप्त करने के अभियुक्त के अधिकार पर बचाव के चरण में विचार किया जाता है और कम से कम आरोप तय करने के चरण में नहीं। हालाँकि, बिना किसी अपवाद के यह कानून का एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है, लेकिन एक अलग तथ्य और स्थिति में, एक अभियुक्त को पुलिस द्वारा जांच पूरी होने और आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के बाद, धारा 91 सीआरपीसी के तहत न्यायालय की शक्ति का आह्वान करने की अनुमति दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **विशेष पुलिस स्थापना बनाम उमेश तिवारी [विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 60404/2021]** में हाल ही में पारित निर्णय से समर्थित है, जिसका निर्णीत समय 21.01.2022 है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अभियुक्त द्वारा धारा 91 सीआरपीसी के तहत दायर एक आवेदन, जिसमें शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों के मोबाइल के माध्यम से कथित रूप से हुई बातचीत के कॉल विवरण प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, को निचली अदालत ने जाँच के लंबित रहने के दौरान ही स्वीकार कर लिया था। अभियोजन पक्ष ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश को चुनौती दी थी। खंडपीठ ने धारा 91 सीआरपीसी के दायरे और अधिकार क्षेत्र पर विस्तृत विश्लेषणात्मक चर्चा के बाद यह निर्णय दिया कि चूँकि जाँच प्रक्रिया एकपक्षीय है और अभियुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए अभियुक्त के कहने पर, जाँच प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान उसे धारा 91 सीआरपीसी का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद, जहाँ से कार्यवाही बहुपक्षीय हो जाती है, अभियुक्त न्यायालय के समक्ष धारा 91 सीआरपीसी का प्रयोग भी कर सकता है। त्वरित संदर्भ के लिए, निर्णय के प्रासंगिक अंश, पैरा संख्या 4.5 और 4.6 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

> "4.5. उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि <u>धारा 91 लागू करने के अधिकार को केवल न्यायालय और पुलिस अधिकारी तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। धारा 91 का दायरा जाँच, पूछताछ, मुकदमे और अन्य कार्यवाहियों में सभी हितधारकों के लिए खुला रहना चाहिए, चाहे वह पीड़ित हो, अभियुक्त हो, पुलिस हो, न्यायालय हो या कोई अन्य संबंधित हितधारक हो।</u>

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

> 4.6. हालाँकि, चूँकि जाँच की प्रक्रिया एकपक्षीय प्रकृति की होती है, जहाँ जाँच के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए अभियुक्त अधिकार के रूप में धारा 91 का प्रयोग नहीं कर सकता। हालाँकि, जाँच के दौरान धारा 91 का प्रयोग न्यायालय, पुलिस या पीड़ित के लिए खुला रहता है, जबकि अभियुक्त आरोप पत्र दाखिल करने के बाद धारा 91 का प्रयोग कर सकता है, जिसके बाद कार्यवाही बहुपक्षीय हो जाती है और अभियोजन पक्ष के अलावा अन्य हितधारकों, अर्थात् पीड़ित और अभियुक्त को भी सामने लाती है।
>
> (जोर दिया गया)

13. यह अब और अधिक एकीकृत नहीं है कि धारा 91 सी.आर.पी.सी. के पीछे सर्वोपरि उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध/मुद्दे से संबंधित कोई भी ठोस सामग्री/प्रासंगिक साक्ष्य, जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के दौरान सत्य की खोज में अनदेखा और बिना विचारे न छोड़ा जाए। जांच/परीक्षण का अंतिम लक्ष्य/आदर्श वाक्य सत्य को उजागर करना और पूर्ण, सही और सच्चे तथ्य की खोज करना है ताकि कोई भी अंधेरे में न रहे। इसलिए, सत्य की खोज करने और निष्पक्ष जांच/परीक्षण के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, धारा 91 सी.आर.पी.सी. के प्रावधान का सहारा न्यायालय या पुलिस द्वारा जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में लिया जा सकता है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नित्य धर्मानंद उर्फ के. लेनिन बनाम गोपाल शीलम रेड्डी [(2018)2 एस.सी.सी 93]** में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "5. यह स्थापित कानून है कि आरोप तय करने के चरण में, अभियुक्त सामान्यतः धारा 91 का आह्वान नहीं कर सकता। हालाँकि, न्याय प्रदान करने और कानून को बनाए रखने के दायित्व के तहत न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाता है, यदि किसी दिए गए मामले में न्याय के हित की आवश्यकता हो, भले ही अभियुक्त को धारा 91 लागू करने का कोई अधिकार न हो। अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए, न्यायालय को यह विश्वास होना चाहिए कि जांचकर्ता के पास उपलब्ध सामग्री, जो आरोप पत्र का हिस्सा नहीं है, आरोप तय करने के मुद्दे पर निर्णायक प्रभाव डालती है।"

15. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **उमेश तिवारी** (सुप्रा) के मामले में धारा 91 सीआरपीसी की विश्लेषणात्मक चर्चा के बाद कानून के एक प्रस्ताव को स्पष्ट किया कि धारा 91 सीआरपीसी को न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर या

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

जांच, पूछताछ, मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही की प्रक्रिया में किसी भी हितधारक के कहने पर लागू किया जा सकता है और हालांकि अभियुक्त को जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसे प्रावधान को लागू करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अभियुक्त को भी प्रावधान लागू करने की अनुमति दी गई थी। इस दृष्टिकोण से, अभियुक्त द्वारा और उसकी ओर से दायर धारा 91 सीआरपीसी के तहत आवेदन पोषणीय है और अन्यथा भी न्यायालय सत्य की खोज करने और अभियुक्तों के साथ न्याय की विफलता को रोकने के लिए सामग्री को स्वतः संज्ञान लेकर बुलाने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। तत्काल संदर्भ के लिए, **उमेश तिवारी** (सुप्रा) के मामले में फैसले का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत है:

> "7. न्यायालय, जाँच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही की प्रक्रिया में, स्वतः संज्ञान लेकर या किसी हितधारक के कहने पर धारा 91 का प्रयोग कर सकता है। धारा 91 के प्रयोग का कारण किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो सकता है, चाहे वह पीड़ित हो, अभियुक्त हो (जांच लंबित रहने के अलावा) या पुलिस। किसी भी हितधारक को धारा 91 के प्रयोग के अधिकार से वंचित करने पर, धारा 91 के मूल उद्देश्य को नकारा जा सकता है, जो सत्य की खोज, न्याय प्रदान करना और न्याय की विफलता को रोकना है। हालाँकि, किसी भी समय किसी भी हितधारक द्वारा ऐसा कोई भी प्रयोग, जाँच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही की प्रक्रिया के लिए उस दस्तावेज़ की आवश्यकता और वांछनीयता की संतुष्टि के अधीन होगा।
>
> 8. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में उत्तरदाता अभियुक्त को जांच लंबित रहने के दौरान धारा 91 लागू करने की अनुमति दी है, जो कि उपरोक्त चर्चा के अनुसार अस्वीकार्य है, क्योंकि जांच की प्रक्रिया एकतरफा है और अभियुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
>
> 9. तदनुसार, यहाँ चुनौती दी गई आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में कायम नहीं रह सकता। हालाँकि, धारा 91 के पीछे के अंतिम उद्देश्य, जो सत्य का पता लगाना, न्याय प्रदान करना और न्याय की विफलता को रोकना है, को देखते हुए, यदि निचली अदालत को लगता है कि आक्षेपित आदेश द्वारा समन के माध्यम से मांगे जाने वाले कॉल विवरण वर्तमान में लंबित जाँच के उद्देश्य से आवश्यक और वांछनीय हैं, तो निचली अदालत जाँच एजेंसी को उक्त सामग्री पर विचार करने का निर्देश देने के लिए स्वतंत्र है ताकि जाँच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जा सके और इसमें शामिल किसी भी हितधारक के प्रति या उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के तत्व के बिना निष्कर्ष निकाला जा सके।"

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

जहाँ तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है, अभियुक्तों द्वारा आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद और आरोप-निर्धारण के चरण से पहले आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, अभियुक्तों द्वारा दायर आवेदन विचारणीय है, क्योंकि न्यायालय को भी धारा 91 सीआरपीसी के तहत आवश्यक सामग्री तलब करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करने का अधिकार है, भले ही अभियुक्तों द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत न किया गया हो। इस प्रकार, किसी भी तरह से, धारा 91 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निचली अदालत द्वारा जारी निर्देशों को दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है या यह नहीं कहा जा सकता है कि वे गलत थे।

16. वर्तमान मामले में, जांच अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह 20.08.2019 को लगभग 03:00 बजे एक साथ करे, जब हत्या की घटना कथित तौर पर उसकी उपस्थिति में सामने आई थी, जैसा कि उसने कहा था। यह निश्चित रूप से प्रमाण का एक अवशिष्ट टुकड़ा है, जो इस मुद्दे से लुप्त हो गया है। डेमो कंपनी से जुड़ा एक ऐसा मोबाइल टावर है, जिससे संबंधित इन कंपनियों का मोबाइल नंबर जांच अधिकारी द्वारा एकत्र नहीं किया गया था और न ही इसे किसी के साथ पेश किया गया था। इसलिए, नामांकित लोगों ने अन्य बातें के साथ-साथ यह कहा गया 28.01.2020 को लागू किया गया कि कंपनी केवल एक वर्ष की अवधि के लिए डेटा रचना है, इसलिए, नामांकित लोगों के मोबाइल से संबंधित कंपनी वैलिड कंपनी से ऐसे मोबाइल टावर लगाने को तालाब बनाना है। विस्तार से, यह वर्तमान आपराधिक मामले में साक्ष्य की आवश्यकता और निष्कासन का हिस्सा है और एक वर्ष की अवधि की अवधि जाने पर ऐसी तारीख कंपनी के रिकॉर्ड में अप्रचलित / हटा दिया जाएगा। इसी तरह, मृत साकिर अली के संबंध में, आरोप के आलोक में कि वह 20.08.2019 को लगभग 03:00 बजे हत्या की घटना के स्थान पर आग्नेयास्त्र संस्थान में था, जबकि असाकिर अली की उपस्थिति यह है कि मृत साकिर अली उस समय पर मौजूद नहीं थे, बल्कि उस समय की सहमति पर वह पुलिस लाइन में मौजूद थे, इसलिए, साकिर अली की उपस्थिति में प्लास्टिक की कंपनी मौजूद थी। साबित करने के लिए, 20.08.2019 को सहयोगियों के साथ सहयोगियों को तलब करने की मांग की गई। इस संबंध में, आवेदन में कहा गया है कि बैंक ने अदालत के आदेश के बिना उन्हें सीतामढी प्रदान करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा, नामांकित आवेदकों ने आवेदन में संकेत दिया है कि क्रिमिनल पिरामिड को आरक्षण पक्ष के निशान के स्तर तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है और उस समय तक, समय समाप्त होने के कारण,

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

नामांकित व्यक्तियों के मोबाइल टावर स्थान और नामांकित-साकिर अली के संबंध में बैपटिस्ट साकिर अली के संबंध में मान्यता प्राप्त / नष्ट हो सकती है, अगर उन्हें एक साथ / समन करने और लगाने का ऑर्डर नहीं दिया जाता है।

17. इस प्रकार, वर्तमान मामले की ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में और जिन चीजों को एकत्र/सम्मन करने की मांग की गई है, उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन को खारिज या स्थगित करना उचित नहीं था, केवल इस आधार पर कि उस पर केवल आरोपी व्यक्तियों के बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण में ही विचार किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। इसके अलावा, जब धारा 91 सीआरपीसी की भाषा स्वयं आरोपी व्यक्ति को धारा 91 सीआरपीसी के प्रावधान को लागू करने के लिए कोई रोक नहीं लगाती है और **उमेश तिवारी** (सुप्रा) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा व्याख्या किए गए अनुपात निर्णय के अनुसार, आरोपी पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर करने के बाद अदालत की शक्ति और क्षेत्राधिकार, धारा 91 सीआरपीसी का आह्वान कर सकता है। इस प्रकार, इस न्यायालय को निचली अदालत द्वारा ऐसी सामग्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने की शक्तियों के प्रयोग में कोई अवैधता या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं लगती है और दिनांक 27.02.2020 का आक्षेपित आदेश, धारा 482 सीआरपीसी के दायरे में, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का औचित्य नहीं रखता है। आक्षेपित आदेश के बने रहने से न तो कोई अवैधता उत्पन्न होती है, न ही आक्षेपित आदेश विधि के विरुद्ध पाया जाता है और न ही इससे न्याय का हनन होता है। निस्संदेह, राज्य/अभियोजन पक्ष ने आक्षेपित आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिसका अर्थ है कि वह विद्वान निचली अदालत के निर्देशानुसार सामग्री प्रस्तुत करने के विरुद्ध नहीं है।

18. जहाँ तक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई अतिरिक्त या वैकल्पिक प्रार्थना का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल काल्पनिक और मान्यताओं व अनुमानों के आधार पर की गई है। यह मानते हुए कि, दिनांक 27.02.2020 के आदेश पारित करने के बाद, सामग्री चार पेन ड्राइव में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है और न्यायालय ने अभियुक्तों को ऐसी पेन ड्राइव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, अभियोजन पक्ष के लिए यह स्वतंत्र है कि वह कार्यवाही के चरण के बारे में स्वयं निचली अदालत के समक्ष आपत्ति उठाए कि ऐसी सामग्री को अभियुक्तों द्वारा साक्ष्य में कब प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह साक्ष्य के दौरान अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आई है। इस प्रकार,

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)

शिकायतकर्ता की ओर से की गई अतिरिक्त/वैकल्पिक प्रार्थना निरर्थक है और इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है।

19. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त चर्चा के साथ, वर्तमान याचिका विफल हो जाती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

20. स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(सुदेश बंसल), जे

रौनक/63

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को सुबह 10:59:50 बजे डाउनलोड किया गया)